

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] No. 226] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 2013/आश्विन 16, 1935 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2013/ASVINA 16, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

विषय : चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गण. और थाइलैंड के मूल के या वहां से निर्यातित "प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड" (पीटीए) के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

सं. 14/7/2013—डीजीएडी.—यतः चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गण. और थाइलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या पीटीए भी कहा गया है) के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच की शुरुआत हेतु मैं. एमसीसी पीटीए इंडिया कॉर्प० प्रा० लि० और मै० रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० (जिन्हें आगे आवेदक कहा गया है) ने संयुक्त रूप से समय—समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय—समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है), के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. और यतः पाटनरोधी जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई "क्षिति" और आरोपित पाटन एवं "क्षित" के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथमदृष्टिया साक्ष्य को मौजूद पाते हैं; इसलिए प्राधिकारी किसी आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लागू किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई "क्षित" को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार, आरोपित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षिति के बारे में एतदद्वारा जांच शुरू करते हैं।

घरेलू उद्योग और उसका आधार

3. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मैं0 एमसीसी पीटीए इंडिया कॉर्प0 प्रा. लि. और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. की ओर से दायर किया गया है । उपर्युक्त घरेलू उत्पादकों के अलावा, भारत में पीटीए का एक और उत्पादक अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. है । तथापि, पीटीए के उक्त घरेलू उत्पादक ने न तो आवेदन का समर्थन किया है और न ही विरोध ।

4331 GI/2013 (1)

4. आवेदन में प्रस्तुत सूचना के अनुसार, मैं० एमसीसी पीटीए इंडिया कॉर्प० प्रा० लि० और मैं० रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० का उत्पादन समान वस्तु के भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक बनता है । आवेदकों ने यह घोषणा की है कि उन्होंने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही भारत में उनके किसी संबंधित पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है । आगे यह घोषित किया गया है कि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक अथवा संबद्ध देशों के संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक से संबंधित नहीं हैं । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आवेदकों ने यह दावा किया है कि वे नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने हेतु मानदंड को पूरा करते हैं । तथापि, मैं० एम सी सी पीटीए इंडिया कार्प प्राठ लि० द्वारा प्रस्तुत सूचना से यह नोट किया जाता है कि यह मित्सुबिशी कैमिकल कार्पोरेशन, जापान की एक सहायक कंपनी है जिसका कोरिया गण. में एक उत्पादक कंपनी में एक बड़ा हिस्सा है । आवेदकों ने यह उल्लेख किया है के कोरिया की इस कंपनी ने एक ग्राहक द्वारा उत्पाद की जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और वही कंपनी विचाराधीन उत्पाद की नियमित निर्यातक नहीं है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि मैं० एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प० प्राठलि० का घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा (आबद्ध खपत को छोड़कर) है और कोरिया की उक्त कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा उसके उत्पादन और बिक्री की तुलना में मामूली है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी मैं० एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प प्राठ लि० को नियम 2(ख) के अंतर्गत एक पात्र घरेलू उत्पादक मानते हैं और तद्नुसार, उसे घरेलू उद्योग मानते हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्न भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है ।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्यूरीफाइट टैरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए) है जिसमें उसके परिवर्तक—मीडियम क्वालिटी टैरेफ्थेलिक एसिड (एमटीए) और क्वालीफाइड टैरेफ्थेलिक एसिड (क्यूटीए) शामिल हैं । विचाराधीन उत्पाद एक सफेद, मुक्त प्रवाही रवादार पाउडर होता है, जो किसी दृश्य संदूषण से मुक्त होता है । टैरेफथेलिक एसिड एक जैविक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र C_6H_4 (COOH) $_2$ है । यह 402^0 से० पर उत्साधित होता है और यह जल एवं अल्कोहल में बमुश्किल विलेय है । पीटीए पॉलिएस्टर चिप्स के विनिर्माण में प्रयुक्त प्राथमिक कच्ची सामग्री है जिसका बाद में उपयोग वस्त्र, पैकेजिंग, साज—सज्जा उपभोक्ता वस्तुओं, रेजिनों और कोटिंग में कई अनुप्रयोगों में होता है । चूंकि क्यूटीए, एमटीए और पीटीए रासायनिक रूप से समान उत्पाद हैं और इसके अलावा, चूंकि इनका उपयोग अदल—बदल कर होता है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में क्यूटीए और एमटीए भी शामिल हैं । आवेदकों ने आगे यह दावा किया है कि डाई मिथाइल टेरेफ्थेलेट (डी एम टी) रासायनिक रूप से एक अलग उत्पाद है, इसलिए यह विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं होता है । विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 29173600 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

समान वस्तु

6. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित और आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा कि आवेदकों ने अनुरोध किया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित प्यूरीफाइड टरेफ्थैलिक एसिड (पीटीए) भौतिक एवं रासायिनक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के रूप में तुलनीय है। आवेदकों ने आगे यह दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस प्रकार इन्हें नियमानुसार "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों / क्षेत्रों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु को "समान वस्तु" मानते हैं।

संबद्घ देश / क्षेत्र

7. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गण. और थाइलैंड हैं । इन्हें वर्तमान जांच में संबद्ध देश / क्षेत्र कहा जा रहा है ।

सामान्य मूल्य

8. आवेदकों ने यह उल्लेख करते हुए संबद्ध देशों के संबंध में सामान्य मूल्य का परिकलन किया है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या भरोसेमंद सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं । आवेदकों ने प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के लिए यथोचित समायोजनों के बाद भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। इस जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है ।

निर्यात कीमत

9. आवेदकों द्वारा निर्यात कीमत का दावा डीजीसीआईएस से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से भारित औसत आयात कीमत के रूप में किया गया है । निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय एवं बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं ।

पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है । इस बात का पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना निर्यात कीमत से अधिक है जिससे यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है । पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक होने का अनुमान है ।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

11. घरेलू उद्योग को हुई क्षिति का निर्धारण करने के लिए आवेदक कंपनियों की सूचना पर विचार किया गया है । आवेदकों ने पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में वृद्धि, कीमत ह्वास, कम कीमत पर बिक्री और घरेलू उद्योग के लाभ, लगाई गई पुंजी पर आय तथा नकद प्रवाह के संबंध में अत्यधिक परिणामी प्रतिकल प्रभाव के रूप में पाटित आयातों के परिणामस्वरूप हो रही क्षित के बारे में

साक्ष्य प्रस्तुत किया है । पाटनरोधी जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही "क्षति" का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है ।

जांच अवधि (पी ओ आई)

12. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अविध 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 (12 माह) की है। तथापि, क्षित जांच अविध पर 1 अप्रैल, 2009 से जांच अविध की समाप्ति तक अर्थात् 2009–10, 2010–11, 2011–12 और जांच अविध के रूप में विचार किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देशों / क्षेत्रों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जिए उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली—110011

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है ।

समय-सीमा

- 15. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जाना चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अध्री है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, ''उपलब्ध तथ्यों'' के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।
- 16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलु उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तृत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

- 17. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग–अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकितं (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' अंकित होना चाहिए ।
- 18. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमित देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
- 19. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और / अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है। 20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई / सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
- 21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजिनक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।
- 22. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं । संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं ।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास ''उपलब्ध तथ्यों'' के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2013

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of 'Purified Terephthalic Acid' (PTA), originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP and Thailand.

No. 14/7/2013-DGAD.—Whereas M/s. MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd., and M/s. Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the applicants) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Purified Terephthalic Acid (hereinafter also referred to as the subject goods or PTA), originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP and Thailand (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority finds existence of prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

- 3. The Application has been filed by M/s. MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd. and M/s. Reliance Industries Limited on behalf of the domestic industry. Apart from the above domestic producers there is one more producer of PTA in India, namely Indian Oil Corporation Limited. However, the said domestic producer of PTA has neither supported nor opposed the application.
- As per the information furnished in the application, the production of M/s. MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd. and M/s Reliance Industries Limited accounts for more than 50% of Indian production of the like article. The applicants have declared that they have neither imported the product under consideration, nor any of their related parties in India have imported the PUC. It has been further declared that the applicants are not related to any of the importers of the subject goods in India or exporters of the subject goods from the subject countries. In view of the above, the applicants have claimed that they satisfy the criteria for considering them as Domestic Industry within the meaning of the Rules. However, it is noted from the information submitted by M/s. MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd. that it is a subsidiary of Mitsubishi Chemical Corpn., Japan, which holds a major share in a producer company in Korea RP. It has been stated by the applicants that this Korean company had exported the subject goods to India during the POI for the purpose of product testing by a customer and the same company is not a regular exporter of the product under consideration. The Authority further notes that M/s. MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd. are holding the largest share of the PUC in the domestic market (excluding captive consumption) and the volume of exports made by the said Korean company is miniscule as compared to their production as well as sales. In view of the above, the Authority considers M/s. MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd. as an eligible domestic producer under rule 2(b) and accordingly treats them as constituting domestic industry. After examining the information on record, the Authority holds that the applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under Consideration

5. The Product under Consideration (PUC) in the present investigation is Purified Terephthalic Acid (PTA), including its variants - Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA). The PUC is a white, free flowing crystalline powder, free from any visual contamination. Terephthalic Acid is an organic compound whose chemical formula is C₆ H₄ (COOH)₂. It sublimes at 402°C and is poorly soluble in water and alcohol. PTA is primary raw material in the manufacture of polyester chips which in turn is used in a number of applications in textile, packaging, furnishings, consumer goods, resins and coatings. Since QTA, MTA and PTA are chemically the same product and further since they are interchangeably used, the scope of the product under consideration covers QTA and MTA as well. The applicants have further claimed that Di-Methyl Terephthalate (DMT) is chemically a different product and therefore not covered in the scope of the product under consideration. The product under consideration is classified under subheading 29173600 of the Customs Tariff Act. However, the customs classification is indicative only and in no way it is binding on the scope of the present investigation.

Like Article

6. The applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the applicants. As submitted by the applicants, the Purified Terephthalic Acid (PTA)

produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicants have further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries/territories.

Subject Countries/Territories

7. The countries involved in the present investigation are China PR, European Union, Korea RP and Thailand. These are being referred to as the subject countries/territories in the present investigation.

Normal value

8. The applicants have constructed the normal values in respect of the subject countries stating that they were unable to get any documentary evidence or reliable information with regard to the domestic prices of the subject goods in the subject countries. The applicants have claimed the normal value on the basis of cost of production in India after due adjustments for the international price of the major raw material. The normal values claimed by the applicants have been considered for the purpose of initiation of this investigation.

Export Price

9. The export price has been claimed by the applicants as the weighted average import price from subject countries based on the import data obtained from the DGCIS. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges to arrive at the net export price.

Dumping Margin

10. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above deminimis.

Injury and Casual Link

11. Information of the applicant companies has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of profits, return on capital employed, and cash flow to the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation (POI)

12. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is from 1st April 2012 to 31st March 2013 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 1st April 2009 to the end of the POI, i.e., 2009-10, 2010-11, 2011-12 and POI.

Submission of Information

13. The known exporters in the subject countries/territories, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties,
Ministry of Commerce and Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi -110011.

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit

15. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is

incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

- 17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
- 18. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
- 19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
- 20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
- 21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

23. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority